लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3850

12 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र निर्यात लक्ष्य 2030

3850. डॉ. सी. एम. रमेश:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2030 तक 9 लाख करोड़ रुपये के वस्त्र निर्यात का लक्ष्य रखा है;

(ख) यदि हाँ, तो विगत पाँच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वस्त्र निर्यात की वर्ष-वार प्रगति क्या है;

(ग) बजट 2025-26 में घोषित कपास प्रौद्योगिकी मिशन उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक है; और

(घ) वस्त्र निर्यात में भारत से आगे कौन से देश हैं और किन क्षेत्रों में भारत उनसे पीछे है और सरकार उक्त क्षेत्रों में समाधान के लिए किस प्रकार योजना बना रही है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क): जी, हाँ। वस्त्र मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक 9 लाख करोड़ रुपये का निर्यात प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।

(ख): पिछले पाँच वर्षों और वर्तमान अवधि के दौरान हस्तशिल्प सहित वस्त्र एवं अपैरल (टी एंड ए) निर्यात का विवरण निम्नानुसार है:

(मूल्य अमरीकी मिलियन डॉलर में)

	2020-21	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26 (अप्रैल-जून)**
कुल वस्त्र एवं अपैरल(टी एंड ए)	29,877	42,347	34,997	34,072	35,988	8,927
हस्तशिल्प	1,708	2,088	1,689	1,802	1,767	399
हस्तशिल्प सहित कुल टी एंड ए	31,585	44,435	36,686	35,874	37,754	9,326

स्रोत: डीजीसीआईएस, अनंतिम डाटा

वित्त वर्ष 2024-25 में वस्त्र एवं अपैरल के निर्यात में वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में लगभग 5.2% की वृद्धि देखी गई है।

(ग): कपास उत्पादकता मिशन को इसके तीन लघु मिशनों के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है, अर्थात, एमएम-I: उत्पादकता और स्थिरता के लिए कपास क्रांति, एमएम-II: गुणवत्ता संवर्धन के लिए कपास क्रांति, और एमएम-III: संबद्ध प्राकृतिक रेशों को बढ़ावा देने के लिए नव्या फाइबर, जिसमें कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई) नोडल मंत्रालय/विभाग है और वस्त्र मंत्रालय भागीदार है।

इस 5-वर्षीय मिशन का उद्देश्य कपास की खेती की उत्पादकता और सस्टेनेबिलिटी में उल्लेखनीय सुधार लाना और एक्स्ट्रा लॉंग स्टेपल कॉटन की किस्मों को बढ़ावा देना है। इससे किसानों को सर्वोत्तम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहायता, किसानों की आय में वृद्धि और भारत के पारंपरिक वस्त्र क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए गुणवत्तापूर्ण कपास की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होने की उम्मीद है। इस प्रकार, इस मिशन से वस्त्र क्षेत्र को अपनी निर्यात प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में सहायता मिलने की उम्मीद है।

(घ): भारत विश्व में वस्त्र उत्पादों का छठा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। चीन, बांग्लादेश, वियतनाम, जर्मनी और इटली दुनिया के शीर्ष 5 निर्यातक देश हैं। भारतीय वस्त्र उद्योग विश्व के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है, जिसमें कपास, रेशम, ऊन, जूट, मानव निर्मित फाइबर सहित प्राकृतिक फाइबरों का एक मजबूत कच्चा माल आधार और फाइबर से फैब्रिक से गारमेंट तक की मूल्य श्रृंखला में विनिर्माण क्षमता है। अस्थिर वैश्विक आर्थिक परिदृश्य और प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में कुछ बाजारों में टैरिफ की कमी के बावजूद, भारत वर्तमान में 220 से अधिक देशों को निर्यात करता है।

सरकार ने भारतीय वस्त्रों को बढ़ावा देने और उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं।

(1) भारत ने 15 मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें भारत और यूके के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित सीईटीए भी शामिल है। इन एफटीए का उद्देश्य टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना और साझेदार बाजारों में भारतीय निर्यातकों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए संरचनात्मक मुद्दों का समाधान करना है।

(2) सरकार शून्य दर वाले निर्यात के सिद्धांत को अपनाकर प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए अपैरल/गारमेंट और मेड-अप्स के लिए राज्य और केंद्रीय करों और लेवी (आरओएससीटीएल) की छूट योजना भी लागू कर रही है। इसके अलावा, आरओएससीटीएल योजना के तहत शामिल नहीं किए गए वस्त्र उत्पाद अन्य उत्पादों के साथ निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (आरओडीटीईपी) के तहत कवर किए जाते हैं। इसके अलावा, सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि के आयोजन और भागीदारी के लिए विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों और व्यापार निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(3) अन्य प्रमुख योजनाओं/पहलों में आधुनिक, एकीकृत, विश्व स्तरीय वस्त्र अवसंरचना का निर्माण करने के लिए पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं अपैरल (पीएम मित्र) पार्क योजना; बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करने के लिए एमएमएफ फैब्रिक, एमएमएफ अपैरल एवं तकनीकी वस्त्रों पर केंद्रित उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना; अनुसंधान, नवाचार एवं विकास, संवर्धन और बाजार विकास पर केंद्रित राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन; समर्थ - वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण हेतु योजना जिसका उद्देश्य मांग-आधारित, रोजगार-उन्मुख, कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करना है; रेशम उत्पादन मूल्य श्रृंखला के व्यापक विकास के लिए सिल्क समग्र-2; हथकरघा क्षेत्र को संपूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम शामिल हैं। वस्त्र मंत्रालय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम और व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना भी क्रियान्वित कर रहा है।

****